आत्म-निर्भरता और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हिमाचल प्रदेश

प्रो. प्रेम कुमार धूमल, मुख्य मंत्री का स्वतन्त्रता दिवस पर आलेख

इस वर्ष हम 62वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1947 को हमारा देश विदेशी दासता की जंजीरें तोड़कर एक स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र बना था। इस ऐतिहासिक दिन का हम सबके लिए विशेष महत्व है। यह हमारे लिए केवल खुशी एवं हर्षोल्लास का ही पर्व नहीं, बल्कि आत्मविवेचन का अवसर भी है कि देश की आन, वान एवं शान के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों तक की बाजी लगा कर जिस भारत का सपना देखा था क्या हम उनके इस सपने को साकार कर पाए हैं। आज का यह दिन हमारे इस बात का प्रण लेने का भी है कि हम देश की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण बनाये रखने के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने से भी नहीं हिचकचायेंगे। छः दशक पूर्व स्वाधीनता हासिल करने के बावजूद आज हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि कुछ विघटनकारी शक्तियां देश की एकता एवं अखण्डता को कमजोर करने के लिए आतुर है। उनके नापाक इरादों से देश कमजोर न हो, इसके लिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के सभी समुदाय जाति एवं धर्म के लोगों में भातृत्व की भावना मजबूत हो, सामुदायिक सद्भाव बना रहे, तभी देश की एकता एवं अखण्डता बनी रहेगी और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।

“ देश स्वतन्त्र होने के लगभग आठ महीने बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का आदर्श ही नहीं माना जाता बल्कि इसने देश के बड़े राज्यों को विकास की राह दिखाई है। देशभर में सेब राज्य की ख्याति अर्जित करने के बाद आज हमारा यह प्रदेश देश का ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में इन वर्षों के दौरान लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।”

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देश में विकास के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज भारत की गिनती विश्व के विकसित देशों में की जाने लगी है। इन उपलब्धियों पर हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में हमें विश्व के साथ आगे बढ़ना होगा।

देश स्वतन्त्र होने के लगभग आठ महीने बाद हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज यह केवल पहाड़ी क्षेत्रों के विकास का आदर्श ही नहीं माना जाता बल्कि इसने देश के बड़े राज्यों को विकास की राह दिखाई है। देशभर में सेब राज्य की ख्याति अर्जित करने के बाद आज हमारा यह प्रदेश देश का ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में इन वर्षों के दौरान लोगों के सामाजिक-आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 30 दिसम्बर, 2007 को प्रदेश की बागडोर सम्भाली है। सत्ता सम्भालते समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना था क्योंकि पूर्व सरकार के कुशासनकाल के दौरान लोग उनके शासन से तंग आ चुके थे। इसके अतिरिक्त दूसरी चुनौती थी विकास को गति प्रदान कर लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इसके दृष्टिगत सरकार ने बागडोर संभालते ही जो पहला निर्णय लिया वह था सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये मासिक करना जिससे प्रदेश के 2,37,250 पात्र लोग लाभान्वित हुए।

मजदूरों की दिहाड़ी को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया। एक अन्य निर्णय के अनुसार विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में उनके लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। कामकाजी महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश सरकार ने उन्हें रक्षा बन्धन तथा भैया-दूज के अवसर पर अवकाश देने के साथ-साथ इन दोनों दिन उनको प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की है। निःसंदेह सरकार के ये प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में है।

प्रदेश सरकार समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। राज्य में अनुसूचित जाति उप-योजना में इसे चालू वित्त वर्ष 157 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे गत वर्ष के 231 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 594 करोड़ रुपये किया गया है, जो राज्य की वार्षिक योजना का 25 प्रतिशत है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत से डा. बी. आर. अम्बेडकर भवनों के निर्माण के लिए 6.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

समाज के निर्धन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 2,82,316 बीपीएल परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाकर उन्हें 30 हजार रूपये प्रति परिवार का बीमा लाभ प्रदान किया गया है, जिसके लिए लाभान्वित परिवारों को 750 रूपये के वार्षिक प्रीमियम में से केवल 30 रुपये ही देने होंगे। मातृ शक्ति बीमा योजना के बीमा लाभ को दोगुना कर, मृत्यु की अवस्था में 50 हजार रूपये तथा किसी अंग की क्षति पर 25 हजार रूपये किया गया है। इसी तरह सरकार ने हथकरघा एवं हस्तशिल्प कल्याण योजना के तहत बुनकरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की है, जिससे प्रदेश के 20 हजार बुनकर परिवार लाभान्वित होंगे।

विकास में सड़कों की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार राज्य में सड़क एवं पुलों के निर्माण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सम्पर्क सड़क सुविधा से जोड़कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2009 के अन्त तक प्रदेश में 500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की जाए। प्रदेश में मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना पुनः शुरू की गई है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में 1365 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत 435 किलोमीटर लम्बे राज्य उच्च मार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों को स्तरोन्नत करने के साथ- साथ राज्य के विभिन्न भागों में दो हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों का रख-रखाव सुनिश्चित बनाया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गों के सौन्दर्यकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में अनेक स्थानों पर 16.85 किलोमीटर लम्बाई की 8 सुरंगों के निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 1853 करोड़ रुपये के वित्त पोषण का मामला 13वें वित्त आयोग को भेजा जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में बेहतर शैक्षणिक माहौल को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों में जनसभाओं, सरकारी समारोहों तथा सामुदायिक भोज के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। 'मिड डे मील' योजना को प्रदेश सरकार तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सभी स्कूलों की अपर प्राईमरी कक्षाओं में आरम्भ किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रथम से दसवीं कक्षा तक से सभी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की गई है, जिससे इस वर्ग के 90 हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत आने वाले खर्चे को प्रदेश तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

प्रदेश के लिए आई.आई.टी. की स्थापना शीघ्र हो, इसके लिए मण्डी के समीप कटौला में जगह का चयन कर लिया गया है, इसके लिए पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा 760 करोड़ रुपये स्वीकृत कर लिए गए हैं। कांगड़ा जिला के देहरा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयास भी जारी है। शिक्षा के इन दोनों श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के खुलने से प्रदेश के विद्यार्थियों को घरद्वार पर ही उच्च शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होगी।

प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित बनाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी में निजी क्षेत्र में मण्डी, ऊना तथा हमीरपुर ज़िलों में तीन मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया है, इसमें हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। मेडिकल कालेज, ज़िला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के अस्पतालों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिए रोगी कल्याण समितियों का पुनर्गठन किया गया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा तथा आई.जी.एम.सी. शिमला में डाक्टरों के अलग-अलग कैडर गठित कर प्रदेश को इन दोनों उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा रही है। कठिन एवं जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों के मौजूदा मानदेय को बढ़ाने के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इन क्षेत्रों के लिए हाल ही में 139 डाक्टरों की नियुक्ति की गई है।

हिमाचल प्रदेश में अपार जल विद्युत क्षमता मौजूद है। प्रदेश सरकार ने राज्य की जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन को सुनिश्चित बनाने के लिए एक वृहद योजना तैयार की है, ताकि इससे और राजस्व की प्राप्ति हो। प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का दोहन होने पर हिमाचल प्रदेश आत्म-निर्भर बनने के साथ-साथ देश का एक खुशहाल एवं समृद्ध राज्य बन जायेगा। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ परियोजनाएं निष्पादन के लिए निजी क्षेत्र को सौंपने तथा 775 मैगावाट की लुहरी जल विद्युत परियोजना को 49 प्रतिशत की राज्य भागीदारी के साथ संयुक्त क्षेत्र में निष्पादित करने का निर्णय लिया है।

प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 30 दिसम्बर, 2007 को प्रदेश की बागडोर सम्भाली है। सत्ता सम्भालते समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना था क्योंकि पूर्व सरकार के शासनकाल के दौरान लोग उनके कुशासन से तंग आ चुके थे। इसके अतिरिक्त दूसरी चुनौती थी विकास को गति प्रदान कर लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित बनाना। इसके दृष्टिगत सरकार ने बागडोर संभालते ही जो पहला निर्णय लिया वह था सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये मासिक करना जिससे प्रदेश के 2,37,250 पात्र लोग लाभान्वित हुए। मजदूरों की दिहाड़ी को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया। एक अन्य निर्णय के अनुसार विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में उनके लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिमाचल प्रदेश तथा यहां के लोगों के प्रति विशेष स्नेह रहा है। उनके प्रधान मंत्रित्वकाल में प्रदेश बहुत लाभान्वित हुआ है, इसके लिए प्रदेशवासी उनके सदैव आभारी रहेंगे। उनके सम्मान स्वरूप प्रदेश सरकार ने बिजली बचत की एक महत्वाकांक्षी योजना का नाम उनके नाम पर रखा है। 80 करोड़ रुपये की इस 'अटल बिजली बचत योजना' का शुभारम्भ आज से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 16 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को चार-चार सी.एफ.एल. बल्ब निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा यह योजना 25 दिसम्बर, 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो जाएगी। इस परियोजना के आरम्भ हो जाने से न केवल ऊर्जा बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में ऊर्जा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा वितरण निगम के गठन का निर्णय लिया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने औद्योगिक पैकेज की अवधि को वर्ष 2013 तक बढ़ाने का मामला भारत सरकार के साथ उठाया है। वर्तमान औद्योगिक पैकेज तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार द्वारा दिया गया था, जिसे यूपीए ने वर्ष 2013 से घटाकर वर्ष 2010 तक सीमित कर दिया था। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यावरणमित्र उद्योगों को स्थापित करने को प्रोत्साहन दे रही है। विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए केवल बंजर भूमि का ही अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है, वह भी स्थानीय लोगों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के नियोजित विकास के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

प्रदेश पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने तथा पर्यावरण संरक्षण में हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है। जलागम, कार्बन में कटौती तथा अन्य पारिस्थितिकीय लाभों की यदि तुलना की जाए तो प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की वन सम्पदा उपलब्ध है। वन सम्पदा के वैज्ञानिक दोहन से प्रदेश को प्रतिवर्ष कम से कम 1000 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। अभी तक हम पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर ही संतोष करते आए हैं। 'क्योटो' प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्बन क्रेडिट के एवज़ में प्रदेश को वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। हमने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के साथ मामला प्रभावशाली ढंग से उठाया है। प्रदेश में औषधीय महत्व की जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा हिमाचल प्रदेश को 'हर्बल राज्य' बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 'जन-जन संजीवनी-वन अभियान-2008' का शुभारम्भ किया गया है।

असीम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल प्रदेश निःसंदेह पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। प्रदेश सरकार पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है क्योंकि इसमें रोजगार एवं स्वरोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पर्यटन की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। धार्मिक, पारिस्थितिकीय, स्वास्थ्य, साहसिक, वन्य प्राणी, हिमालयन धरोहर एवं ग्राम्य पर्यटन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश को पर्यटन गतिविधियों से सम्बद्ध करने के दृष्टिगत 'हिमाचल प्रदेश होम स्टे स्कीम-2008' आरम्भ करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को व्यापक बढ़ावा देना है।

प्रदेश सरकार ने कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों से देय 50 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करने का निर्णय लिया है। किसानों को उपयुक्त फसल पैदा करने के लिए परामर्श देने के लिए चालू वित्त वर्ष से प्रदेश में 'मिट्टी परीक्षण कार्ड' योजना आरम्भ की गई है। अभी तक 56 हजार किसानों की भूमि का परीक्षण किया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भूमि जांच के बाद किसानों को एक लाख कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा राज्य में अतिरिक्त आय सृजन के लिए राज्य सरकार ने पांच सौ करोड़ की एकीकृत कृषि परियोजना वित्त पोषण के लिए जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉरपरेशन को भेजी है।

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत एक महत्वूपर्ण निर्णय के तहत प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कृषकों एवं बागबानों को दस लाख रुपये तक के ऋण हेतु उनकी मॉर्डगेज डीड पर पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प डियूटी में छूट देने का निर्णय लिया है, इससे प्रदेश के किसानों को 35 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ मिलेंगे।

बागबानों को उनके उत्पाद को उचित मूल्य सुनिश्चित बनाने के दृष्टिगत किन्नू, माल्टा, आम, सेब आदि के समर्थन मूल्यों में 50 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है। सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए 27 करोड़ रुपये की 'ऐंटी हेल गन' खरीदने की परियोजना वित्त पोषण के लिए भेजी गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अप्रैल, 2008 से प्रदेश के सभी 12 ज़िलों में लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलेगा।

प्रदेश के विकास में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत हमारी सरकार के कर्मचारियों के साथ हमेशा सौहार्दपूर्ण सम्बंध रहे हैं। कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के दृष्टिगत, हमने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को 5 प्रतिशत 'अंतरिम राहत' जारी की है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों को 300 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्राप्त हुए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू की गई है। विभिन्न विभागों में आठ वर्ष का सेवाकाल पूरे कर चुके दिहाड़ीदारों की सेवाएं चरणबद्ध रूप से नियमित की जा रही हैं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा लोक निर्माण विभाग में दस वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके 13,205 दिहाड़ीदारों की सेवाएं नियमित की गई हैं।

प्रदेश सरकार विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बना रही है ताकि युवा क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास में किया जा सके। सरकार ने तकनीकी एवं व्यावसायिक पदों को 50 प्रतिशत बैच आधार पर तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश की सभी जल विद्युत परियोजनाओं एवं औद्योगिक इकाइयों में 70 प्रतिशत रोजगार के अवसर स्थानीय बेरोजगारों युवाओं को प्रदान करना सुनिश्चित बनाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के लिए तीन भारतीय रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई जिनमें एक बटालियन केवल महिलाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इससे प्रदेश के लगभग तीन हजार युवाओं को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र में ही विभिन्न श्रेणियों के 26 हजार पद भरे जाएंगे।

हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों की है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर देश का नाम रोशन किया है। प्रदेश सरकार ने सैनिक कल्याण के नाम से एक नया विभाग गठित किया है, जिसका उद्देश्य भूतपूर्व एवं सेवारत सैनिकों की कल्याण गतिविधियों का अनुश्रवण करना है।

पड़ौसी राज्यों के साथ परस्पर हित के अनेक मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के प्रयास किए गए हैं इससे अन्तरराज्यीय मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में सरकार सफल रही है। चंडीगढ.-बद्दी मार्ग का निर्माण जून, 2009 तक पूरा करना, बद्दी तथा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली को सुपर हाईवे से जोड़ना, श्री आनन्दपुर साहिब एवं श्री नैणा देवी जी को रज्जू मार्ग से जोड़ना जैसे मामले पंजाब सरकार के साथ उठाए गए हैं। पंजाब सरकार हिमाचल प्रदेश को सर्दियों में 300 मैगावाट बिजली देने को सहमत हो गई है, हिमाचल प्रदेश गर्मियों में इतनी ही बिजली पंजाब को देगा। देश के सभी पर्वतीय राज्यों के साझा हितों एवं समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करने के लिए ट्रांस हिमालयन विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया गया है। पठानकोट एवं जोगिन्द्रनगर के बीच मौजूदा नैरोगेज़ रेल लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने, इसका विस्तार लेह-लद्दाख तक करने का मामला भी केन्द्र सरकार से उठाया गया है। यह रेल मार्ग आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि चीन द्वारा ल्हासा को बीजिंग से ब्रॉडगेज़ रेल लाईन से जोड़ा जा चुका है। यह रेल लाईन सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ विकास आवश्यकताओं को भी पूरा करेगी। केन्द्र का इस ओर सकारात्मक रुख है। प्रदेश सरकार ने रोहतांग सुरंग का निर्माण कार्य आरम्भ करने तथा जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य को जायज हिस्सा प्रदान करने का मामला केन्द्र सरकार से प्रभावशाली ढंग से उठाया है।

आपकी सरकार प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित विकास तथा लोगों के सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं, समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आओ! हिमाचल प्रदेश को देश का एक विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करें। सरकार के प्रयास तभी फलीभूत होंगे जब इसमें जन सहयोग होगा।

आपकी सरकार प्रदेश के तीव्र एवं संतुलित विकास तथा लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं, समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आओ! हिमाचल प्रदेश को देश का एक विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करे। सरकार के प्रयास तभी फलीभूत होंगे जब इसमें जन सहयोग होगा।